अब सौ से अधिक आबादी वाले मजरे, टोले सड़क से जुड़ेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 11 मार्च, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल शुरू की है.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सुगम संपर्कता परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से गांव, ग्राम पंचायत और 100 से अधिक आबादी वाले मजरा-टोला तथा मुख्यमंत्री मजरा-टोला योजना के तहत चिन्हित बस्तियों को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा. परियोजना अंतर्गत सड़कों का निर्माण मनरेगा यानी बीबी-जीरामजी योजना के माध्यम से कराया जाएगा. इसके लिए प्रदेश की प्रत्येक जनपद पंचायत को रुपए 3 करोड़ तक की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है. मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा सभी जनपद पंचायतों को राशि भी आवंटित कर दी गई है. परियोजना के तहत मजरे-टोले और सांदीपनि विद्यालयों तक बनने वाली सड़कों के लिए स्थान का चयन सिपरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा. साथ ही सड़कों की डीपीआर तैयार करने के लिए सिपरी सॉफ्टवेयर और आरआईएमएस का उपयोग किया जाएगा.

ड्रोन से होगी निगरानी

परियोजना के तहत बनने वाली सड़कों की निगरानी ड्रोन तकनीक से की जाएगी. निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

28 तक डीपीआर तैयार करने के निर्देश

आयुक्त मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद अवि प्रसाद ने बताया कि परियोजना के तहत 28 मार्च तक डीपीआर तैयार कर उसकी तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए.

सागर में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का शुभारंभ

भोपाल/सागर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में शिक्षा का नया अध्याय लिखा जा रहा है और ज्ञानवीर विश्वविद्यालय युवाओं के सपनों को नई ऊंचाई देने का माध्यम बनेगा. उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति ज्ञान और मूल्यों पर आधारित रही है और तक्षशिला तथा नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसार किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है. उन्होंने महान शिक्षाविद् डॉ. हरि सिंह गौर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से सागर में शिक्षा का नया सूर्योदय हुआ और यहां से पढ़े विद्यार्थी देश-विदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं. सागर में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने राहतगढ़ और जेसीनगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए आधुनिक लाइब्रेरी बनाने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय बुंदेलखंड के युवाओं के सामर्थ्य और संकल्पों को नई दिशा देगा. मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत की सराहना करते हुए कहा कि ज्ञानवीर विश्वविद्यालय अपने माता-पिता के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक है.

अंजना हत्याकांड में अब सीबीआई करेगी जांच

नई दिल्ली/सागर. सागर जिले के बरोदिया नौनागिर के के बहुचर्चित अंजना हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने मध्य प्रदेश पुलिस की जांच थ्योरी को नकारते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने यह आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सबसे बड़ी लापरवाही तब सामने आई जब मुख्य गवाह अंजना की मौत हुई. चाचा राजेंद्र का शव एम्बुलेंस से लाते समय उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने इसे गाड़ी से गिरना बताकर केस रफा-दफा करने की कोशिश की.

सिलेंडर की जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई

मंत्री गोविन्द सिंह ने सभी कलेक्टर्स को दिए निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 11 मार्च, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नही हो, इस हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं.

उन्होंने कहा है कि सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में वितरक स्तर पर एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की स्थिति निर्मित नहीं हो. राजपूत ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है एवं आपूर्ति बनी हुई है.

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के कारण आयात में हुई रुकावट को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि एलपीजी की आपूर्ति एवं विपणन केवल घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को किया जाये. ऑयल कम्पनियों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये वितरण प्रणाली में कुछ उपाय शुरू किये गये हैं. अब पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही रिफिल बुकिंग स्वीकार की जा रही है. इसका उद्देश्य कालाबाजारी और अफरा-तफरी को रोकना तथा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से समान वितरण सुनिश्चित करना है. इन परिस्थितियों में ऑयल कम्पनियों द्वारा तय किया गया है कि वर्तमान में चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा किसी और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (होटल, मॉल, वल्क एलपीजी का उपयोग करने वाले औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्री आदि) को कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई नहीं की जायेगी.

> सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि जिला स्तर पर खाद्य विभाग तथा ऑयल कम्पनी के अधिकारी और एलपीजी वितरकों के साथ नियमित रूप से बैठक कर वाणिज्यिक और घरेलू सिलेण्डर की उपलब्धता की समीक्षा करें. जिले के बड़े वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की भी बैठक कर उनके पास उपलब्ध स्टॉक का विवेकपूर्ण उपयोग करने एवं उनकी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वैकल्पिक ईंधन आपूर्ति/स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी जाये.

एसीएस स्वास्थ्य की अध्यक्षता में समिति गठित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल,11 मार्च. राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए प्रस्तावित समग्र स्वास्थ्य योजना के अंतिम प्रारूप, नीति निर्धारण के साथ ही कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों से परामर्श कर योजना को मंत्रि-परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य जबकि आयुक्त

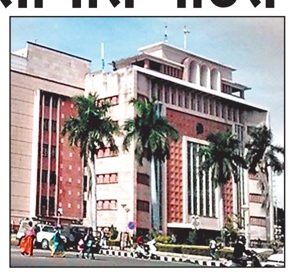

लोक स्वास्थ्य सदस्य-सचिव होंगे. समिति प्रस्तावित योजना के सभी आवश्यक तत्वों जैसे पात्रता, कवरेज, वित्तीय माडल, क्रियान्वयन संरचना तथा हितधारकों के परामर्श को समाहित कर विस्तृत योजना दस्तावेज तैयार करेगी, जिसे मंत्रि-परिषद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.

परियोजनाएं समय में, गुणवत्ता के साथ पूरी हों

भोपाल, 11 मार्च. तुलसीराम सिलावट ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में और पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि समय पर परियोजनाएं पूरी होने से जनता को उनका लाभ मिल सकेगा. साथ ही अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ताकि कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई न हो. मंत्री सिलावट ने मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली. बैठक में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी

और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. बैठक में नर्मदा-ताप्ती कछार इंदौर, जल संसाधन विभाग उज्जैन और नमामि क्षिप्रा परियोजना इकाई उज्जैन के अंतर्गत निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की समीक्षा की गई.

मंत्री ने आगामी सिंहस्थ-2028 से जुड़े कार्यों—कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना, सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना और क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर घाट निर्माण—की प्रगति की जानकारी लेकर इन्हें समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए.

परियोजनाओं के पूर्ण होने पर उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, झाबुआ, बुरहानपुर और धार जिलों में लगभग 5.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी. मंत्री ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं की 15-15 दिन में समीक्षा कर तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए.

संघ में नई संगठनात्मक संरचना की आहट, कल से होगी बैठक

इंदौर, 11 मार्च. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हरियाणा के समालखा में 13 से 15 मार्च तक आयोजित होगी. संघ के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें संगठन की कार्यप्रणाली और ढांचे में संभावित बड़े बदलावों पर चर्चा की जाएगी. यह प्रतिनिधि सभा संघ की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था मानी जाती है, जहां संगठन की भविष्य की दिशा तय होती है. सूत्रों के अनुसार संघ अपनी पारंपरिक संगठनात्मक संरचना में बदलाव पर विचार कर रहा है. अभी तक संघ की व्यवस्था क्षेत्र, प्रांत और विभाग जैसी इकाइयों के आधार पर संचालित होती रही है.

लोक अदालत मध्यस्थता का सर्वोत्तम मंच : खण्डेलवाल

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 11 मार्च। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अतुल कुमार खण्डेलवाल के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय सिंगरौली एवं तहसील न्यायालय देवसर तथा सरई में 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक आदालत में अधिक से अधिक प्रकरण के निराकरण एवं नेशनल लोक अदालत के समुचित प्रचार-प्रसार के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा जिला न्यायालय परिसर में वैकल्पिक विवाद समाधान सहायता प्वॉइंट का शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री खण्डेलवाल ने

कहा कि प्रत्येक न्यायाधीश एवं अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि सभी पक्षकारों को सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्राप्त हो। सुलभ एवं त्वरित न्याय प्राप्त करने के लिये लोक अदालत एवं मध्यस्थता सर्वोत्तम मंच हैं। 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।

इनकी रही उपस्थिति

इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश अतुल कुमार खंडेलवाल सहित कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश प्रिवेंद्र कुमार सेन, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजेन्द्र देव पांडेय, कंचन गुप्ता द्वितीय जिला न्यायाधीश, खालिद मुहतरम अहमद प्रथम जिला एवं अति सत्र न्यायाधीश, अरूण कुमार खरादी पंचम जिला एवं अति सत्र न्यायाधीश, धर्मेन्द्र कुमार सोनी तृतीय जिला एवं अति सत्र न्यायाधीश, उमेश सोनी सप्तम जिला एवं अति सत्र न्यायाधीश, शिवचरण पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोरमा तिवारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मौजूद रहे.

एनएच 30 से लोहरा गांव मार्ग पर टूटी नाली बनी खतरा, प्रशासन मौन

नवभारत न्यूज

चाकघाट, 11 मार्च. एनएच-30 से लोहरा गांव की ओर जाने वाली सड़क पर बना नाली का स्लैब लंबे समय से टूटा हुआ पड़ा है। इस कारण सड़क पर आने-जाने वाले लोगों, स्कूली बच्चों एवं वाहन चालकों को लगातार परेशानी और दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बीच में इस नाली की मरम्मतक गई लेकिन शायद वह सिर्फ खानापूर्ति ही थी जिस कारण से यह नाली का स्लैब दोबारा टूट गया।टूटी हुई नाली के कारण सड़क का किनारा कमजोर हो गया है। बरसात के समय पानी भरने से स्थिति और भी गंभीर हो सकती हैं, जिससे सड़क धंसने और वाहनों के फिसलने का खतरा बढ़ सकता है है। खासकर रात के समय यहां से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह स्थान काफी जोखिम भरा बन गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग लोहरा गांव सहित आसपास के कई गांवों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है।

प्रतिदिन इस सड़क से बड़ी संख्या में लोग अपने काम, स्कूल और बाजार के लिए आते-जाते हैं। इसके बावजूद टूटी नाली की मरम्मत को लेकर जिम्मेदार विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है।स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए और टूटी नाली की मरम्मत कराई जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

OFFICE OF SE (O&M) CIRCLE
M.P.P.K.V.V.C.L., SIDHI
REGD. OFFICE - BLOCK No. 8TH, 3RD FLOOR, SHAKTI BHAWAN, RAMPU R, JABALPUR - 482 008 (M.P.)
CIN: U40109MP2002SGC015120
(E-mail:- seonmsidhi@yahoo.co.in)

विद्युत् प्रद्योति

1912

No. SE/SDI/PUR/4811 Dtd: 09.03.2026

NOTICE INVITING TENDER

Tender are invited as following :

Sr. No	Tender Specification No	Name of the Work/ services	Approx. Value (Rs. In Lakh)	Tender Fees (In Rs.)	Due date of opening of tender online from 14:00 Hrs.*
1	SE/SDI/PUR/ 4811 (e-Tender No.2026_PK VVC _488129_1)	Empanelment of contractors to award a Contract for survey, installation, testing and commissioning of 11 kV line, 11/0.433 kV distribution transformer and LT line under different	168.05	5000 + GST 18%	25.03.2026

* For other details please visit website http://www.mptender.gov.in.

Superintending Engineer (O&M)
MPPKVVCL, Sidhi

प्रदेश के कई जिलों में पारा 38 डिग्री पार

चिलचिलाती धूप से राहगीर परेशान, ग्वालियर-चंबल सबसे ज्यादा प्रभावित

भोपाल, 11 मार्च. मध्यप्रदेश में इस वर्ष मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने तेजी से असर दिखाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है.

सबसे ज्यादा असर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में देखा जा रहा है, जहां तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है. भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में भी दिन का पारा लगातार बढ़ रहा है. प्रदेश भर में चिलचिलाती धूप से आम आदमी को काफी परेशानी का समना करना है .

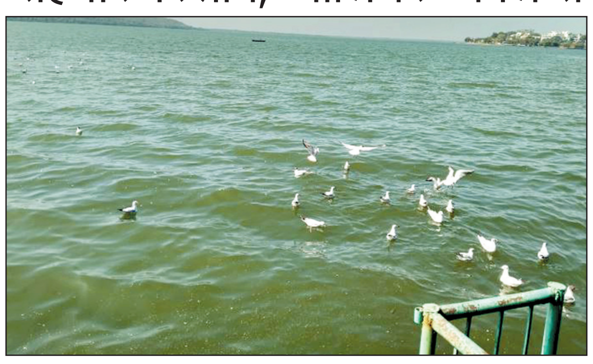

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के कई शहरों में तापमान 38 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया. धार में सबसे अधिक 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा सागर में 38.9 डिग्री, रतलाम और नर्मदापुरम में 38.8 डिग्री, खजुराहो में 38.3 डिग्री, गुना में 38.1 डिग्री तथा दमोह और टीकमगढ़ में 38 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

> पांच बड़े शहरों में ग्वालियर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 37.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. उज्जैन में 37 डिग्री, इंदौर में 36.8 डिग्री, जबलपुर में 36.6 डिग्री और भोपाल में 36.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. प्रदेश में हवा की दिशा बदलने के कारण गर्मी में तेजी आई है. पहले हवाएं उत्तर-पूर्व दिशा से आ रही थीं, लेकिन अब पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की ओर से चल रही हैं. इन हवाओं में नमी कम है और यह राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से होकर मध्यप्रदेश पहुंच रही हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ रहा है.

कार्यालय नगर परिषद् मऊगंज जिला मऊगंज (म.प्र.)

Cmomahuganj@mpurban.gov.in

क्रमांक/3475/e-tendering/NP/2026 मऊगंज दिनांक 11.03.2026

निविदा सूचना-प्रथम आमंत्रण

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से आनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है. निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट:https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है.

क्र.	टेण्डर क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1.	2026_UAD_489355_1 दिनांक-11.03.2026	Interception & Diversion of Nallahs with STP works Project of Mauganj town under SBM 2.o	1. 365 दिवस 2. 6,47,19,000/-	1.20000/- 2.323595/-	13.04.2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन आनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जायेगा. पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा.

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् मऊगंज
जिला-मऊगंज (म.प्र.)

पेज एक का शेष

अविश्वास प्रस्ताव खारिज

मैं विपक्ष नेता से पूछना चाहता हूं कि आप तब क्यों नहीं बोले. किसने रोका था. वो तो आपका अधिकार है कि आपकी पार्टी से कौन बोलेगा.

➡वक्फ संशोधन-धारा 370 जैसी चर्चाओं से राहुल गायब रहे. एसआईआर पर चर्चा थी. विपक्ष के नेता को बोला गया कि आप बोलिए. नहीं बोले. उन्होंने सदन डिस्टर्ब किया.

➡16वीं लोकसभा में राहुल गांधी ने 2014, 2015, 2017 और 2018 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग नहीं लिया. उन्होंने 16वीं लोकसभा में केंद्रीय बजट पर किसी भी चर्चा में भी हिस्सा नहीं लिया.

➡उन्होंने किसी भी सरकारी विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया. 16वें, 17वें, 19वें, 20वें और 21वें सत्रों में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग नहीं लिया. 19वें, 20वें, 22वें और 23वें सत्रों में उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग नहीं लिया और एक विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधायी चर्चा में भी भाग नहीं लिया. 18वीं लोकसभा में उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग नहीं लिया.

दो राज्यों को 16,450 करोड़ की सौगात

पीएम मोदी ने एलपीजी संकट की अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं होने देंगे. भारत संकट अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता : प्रधानमंत्री ने कहा, खाड़ी क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए आपकी चिंताएं स्वाभाविक हैं. हमारे लाखों भाई-बहन वहां काम करते हैं.

परिणय सूत्र में बंधे 176 जोड़े

झाबुआ. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जनपद पंचायत रामा में भव्य सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

कार्यक्रम में मप्र शासन की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई और नवविवाहित दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की.

इस अवसर पर आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में कुल 176 जोड़े विवाह बंधन में बंधे, जिनमें रामा क्षेत्र के 84 जोड़े एवं रानापुर क्षेत्र के 92 जोड़े शामिल रहे.

पूरे कार्यक्रम का आयोजन पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जहां नव-दंपतियों और उनके परिजनों में विशेष उत्साह देखा गया. विवाह विधि-विधान से गायत्री परिजनों द्वारा संपन्न करवाया गया.

कार्यालय नगर परिषद् अमरपाटन जिला मैहर (म.प्र.)

E-mail-cmoamarpatan@mpurban.gov.in

क्रमांक/2606/ई.नि./न.परि./अमरपाटन/2025-26 अमरपाटन, दिनांक 06.03.2026

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

एतद द्वारा निगर परिषद् अमरपाटन निम्नांकित कार्यों के लिए पंजीकृत ठेकेदारों/प्रतिष्ठानों से ई- टेण्डरिंग के माध्यम से प्रपत्र -अ में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में प्रचलित दर सूची के आधार पर आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है. विवरण निम्नानुसार है.:-

क्र.	सिस्टम नं.	कार्य का नाम एवं विवरण	अनुमानित राशि (लाख में)	धरोहर राशि रु.	कोरे निविदा फार्म की कीमत रु.	निविदा समयावधि	निविदा का प्रकार
1.	2026_UAD_ 488866_1	वार्ड क्र. 4 पुरानी तहसील के सामने दुकान निर्माण कार्य	134.50	100905.00/-	10000.00/-	30 दिवस	प्रथम

नोट:- उक्त कार्य निविदा प्रपत्र दिनांक 10.03.2026 को 10.30 A.M. बजे से दिनांक 09.04.2026 को समय 5.30 P.M. तक वेबसाइट पर आनलाइन भुगतान कर प्राप्त हो सकेंगे. विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in/ पर देखी जा सकती है. किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट में देखा जा सकता है.

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् अमरपाटन
जिला-मैहर (म.प्र.)